SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED

Regd. Office: "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata 700 019 CIN: [illegible] Tel No.: [illegible] Fax No.: [illegible] Website: www.speciality.co.in Email: corporate@speciality.co.in

Extract of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2018

Rs. in Lakhs (Except per share data)

| Sr. No. | Particulars | Standalone: For the Quarter ended on 30.06.2018 (Unaudited) | 31.03.2018 (Refer Note 4) | 30.06.2017 (Unaudited) | Standalone: Previous Year ended on 31.03.2018 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total income from operations | 7,600 | 7,297 | 7,221 | 29,679 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before exceptional item and tax) | (574) | (742) | (847) | (2,101) |
| 3 | Exceptional item (Refer note 1) | - | - | 835 | 1,014 |
| 4 | Net Profit / (Loss) before tax for the period (after exceptional item) | (574) | (742) | (1,682) | (3,115) |
| 5 | Net Profit / (Loss) after tax for the period (after exceptional item) | (574) | (2,988) | (1,592) | (3,341) |
| 6 | Total comprehensive income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)) | (575) | (2,883) | (1,601) | (3,304) |
| 7 | Paid-up equity share capital (face value of ₹ 10 per share) | 4,696 | 4,696 | 4,696 | 4,696 |
| 8 | Earnings per equity share (of ₹ 10/- each) (not annualised for quarters) | | | | |
| | (a) Basic | (1.22) | (6.32) | (3.37) | (11.37) |
| | (b) Diluted | (1.22) | (6.32) | (3.37) | (11.37) |

Notes:

1. Exceptional item relates to the impairment of investments and receivables of the joint venture company.
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. To make the same available on the websites of the Stock Exchanges on which the Shares of the Company are listed namely www.bseindia.com and www.nseindia.com. The full format of the said results are also available on the Company's website www.speciality.co.in.
3. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10 August 2018.
4. The figures of the March 2018 quarter are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year March 2018 and the published year to date figures upto December 2018 (Third Quarter) of the March 2018 financial year.

Place: Mumbai
Date: 10 August 2018

For and on behalf of the Board
For Speciality Restaurants Limited
Indranil Chatterjee
Director - Commercial Operations
(DIN : 00200577)

SPICERY

# औद्योगिक उत्पादन 5 माह के उच्च स्तर पर

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 10 अगस्त

देश का औद्योगिक उत्पादन जून महीने में 7 प्रतिशत बढ़ा है। यह पिछले 5 महीने का उच्चतम स्तर है। विनिर्माण क्षेत्र में तेजी और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हुआ है।

जून महीने में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) इसके पहले के मई महीने की तुलना में करीब दोगुना बढ़ा है। मई में 3.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। तेजी की प्रमुख वजह विनिर्माण क्षेत्र है, जिसकी हिस्सेदारी सूचकांक में 77.6 प्रतिशत है। विनिर्माण में 6.9 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई, जो मई में महज 2.8 प्रतिशत थी।

विनिर्माण के 23 उपक्षेत्रों में सिर्फ 4 में सालाना आधार पर दबाव देखा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, औषधि, खाद्य, धातु, गैर धातु उत्पाद आदि क्षेत्रों का बेहतर प्रदर्शन जारी है।

अर्थशास्त्रियों को लगता है कि विनिर्माण क्षेत्र में शानदार वृद्धि दर आधार के असर से दिख रही है। इस क्षेत्र ने 2017 में इस दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी।

केयर रेटिंग्स में मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, 'प्रगति बेहतरीन है। देखना यह है कि तेजी बरकरार रहती है या नहीं। पिछले साल जीएसटी लागू होने के पहले जून महीने में स्टॉक खत्म करने की कवायद हुई थी और उत्पादन में कटौती हुई थी। अगर यही दरें अगली 2-3 तिमाही तक बरकरार रहती हैं तो हम इस साल 5-6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, जो उल्लेखनीय तेजी होगी। जुलाई और अगस्त महीने में खपत में सुस्ती नजर आ सकती है, जो त्योहारी सीजन में एक बार फिर बढ़ेगी, जो अगस्त के आखिर से शुरू होती है।'

दूसरी तरफ जून में खनन 6.6 प्रतिशत बढ़ा है, जो आशा के अनुरूप है। इसके साथ ही बिजली उत्पादन 8.5 प्रतिशत बढ़ा है, जो जून के 4.2 प्रतिशत के दोगुने से ज्यादा है।

संवेदनशील पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में 9.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे निवेश जुड़ा होता है। यह पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सुस्ती दूर होने के संकेत हैं। मई में इस क्षेत्र में 7.56 प्रतिशत की तेजी आई थी, जो अप्रैल के 11.9 प्रतिशत से कम थी। इसी तरह बुनियादी ढांचा/निर्माण क्षेत्र में भी तेजी आई है। जून महीने में इसमें 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो मई के 4.9 प्रतिशत की तुलना में बहुत ज्यादा है, जब सीमेंट और स्टील का उत्पादन घटा था।

भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजित बनर्जी ने कहा, 'उत्साहजनक खबर यह है कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और बुनियादी ढांचा-निर्माण क्षेत्र में तेजी है। पिछले साल के कम आधार के बावजूद सड़क, रेलवे और सस्ते आवास क्षेत्र में यह निवेश की सकारात्मक धारणा दिखाता है। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ने के भी संकेत हैं।'

बहरहाल मध्यावधि के हिसाब से वृद्धि की स्थिति साफ नहीं है। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने कहा, 'प्राथमिक वस्तुएं- जो औद्योगिक वृद्धि की प्रमुख सूचक हैं, बेहतरीन वृद्धि दिखा रही हैं और टिकाऊ औद्योगिक तेजी का विश्वास दिलाती हैं। लेकिन मध्यवर्ती वस्तु, जो अन्य प्रमुख संकेतक हैं, इस बात का भरोसा नहीं जगा रही हैं कि औद्योगिक वृद्धि टिकाऊ होगी। बहरहाल लगातार दूसरे साल मॉनसून बेहतर रहने, ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य और बुनियादी ढांचे व हाउसिंग पर सरकार की ओर से ध्यान दिए जाने से मांग की स्थिति बेहतर बने रहने की संभावना है।'



## आईआईपी में मजबूती

- जून में 7 प्रतिशत बढ़ा औद्योगिक उत्पादन, मई में था 3.92 प्रतिशत
- पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में शानदार प्रदर्शन, कुल मिलाकर विनिर्माण गतिविधियों में तेजी से वृद्धि को मिला बल
- जून में खनन 6.6 प्रतिशत बढ़ा
- बिजली उत्पादन 8.5 प्रतिशत बढ़ा
- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में 9.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई

ORTEL COMMUNICATIONS LIMITED

Registered Office: 87/122A, Safdarjung Enclave, New Delhi – 110029
Corporate Office: C-1, BDA Colony, Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Odisha - 751016
Phone: 0674-7107250 Mail Id: ipo@ortelgroup.com
CIN: L74899DL1995PLC069353

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2018

(Rs. in Lakhs)

| Sl. No. | Particulars | Quarter ended 30-Jun-18 (Unaudited) | 31-Mar-18 (Audited) | 30-Jun-17 (Unaudited) | Year ended 31-Mar-18 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Income from operation (Net) | 3,134.98 | 3,986.89 | 4,962.74 | 18,403.56 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items) | (1,442.25) | (1,098.14) | (1.48) | (1,649.96) |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items) | (1,348.22) | (8,016.34) | (285.44) | (9,533.09) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items) | (1,348.22) | (8,016.34) | (285.44) | (9,533.09) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (1,296.58) | (7,949.65) | (281.29) | (9,454.48) |
| 6 | Equity share capital (Face value of Rs.10/- each) | 3,297.69 | 3,047.69 | 3,047.69 | 3,047.69 |
| 7 | Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the audited balance sheet of the previous year | - | - | - | - |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)* | | | | |
| | Basic | (4.27) | (26.32) | (0.94) | (31.29) |
| | Diluted | (4.27) | (26.32) | (0.94) | (31.29) |

Notes:

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results and segment results together with Limited Review Report are available on the Stock Exchange websites i.e.www.bseindia.com & www.nseindia.com and on Company's website www.ortelgroup.com. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 10th August, 2018.

2) Figures of Previous Period have been regrouped/reclassified wherever necessary to facilitate comparison.

For and on behalf of the Board of Directors
Ortel Communications Limited
Sd/-
Jyoti Bhusan Pany
Chairman cum Independent Director

Place : Bhubaneswar
Date : 10.08.2018

Adfactors 254

बैंक ऑफ इंडिया

# एथनॉल बचाएगा विदेशी मुद्रा

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 10 अगस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अगले 4 साल में एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम से कम से कम 12,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। दिल्ली में विश्व जैव ईंधन दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 2022 तक ईंधन में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने और 2020 तक इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य रखा है। इससे देश के तेल आयात बिल में बचत होगी, जो कच्चे तेल बॉस्केट का मूल्य 65 डॉलर प्रति बैरल रहने पर 2017-18 में 24 प्रतिशत बढ़कर 88 अरब डॉलर और 2018-19 में बढ़कर 109 अरब डॉलर होने की उम्मीद है।

यह ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत 100 अरब रुपये के निवेश से 12 जैव ईंधन रिफाइनरी स्थापित करने की योजना बना रहा है, सरकार ने एथेनॉल और बायोडीजल पर वस्तु एवं सेवा कर 18 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 15 प्रतिशत और 12 प्रतिशत कर दिया है। मोदी ने कहा कि 2022 तक भारत में एथेनॉल उत्पादन तीन गुना बढ़कर 4.5 अरब लीटर हो जाएगा, जो अभी 1.41 अरब लीटर है। इस समय भरत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए 80 प्रतिशत आयात पर निर्भर है।

मोदी ने कहा कि इस समय एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से देश 40 अरब रुपये विदेशी मुद्रा बचा रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। आगामी 12 रिफाइनरी सरकारी कंपनियों- एचपीसीएल (4), आईओसीएल (3), बीपीसीएल (3), एमआरपीएल (1) और नूमालीगिरि रिफाइनरी (1) की होंगी। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे सीएमसी बायोरिफाइनरीज और जैव इनोगी 10-10 इकाइयां स्थापित कर रही हैं, जबकि केम पोलिस एक इकाई स्थापित करेगी। निजी क्षेत्र की कुछ अन्य कंपनियां भी 2022 तक इकाइयां स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। कुल 28 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से 16 निजी क्षेत्र की और 12 सरकारी हैं।

मोदी ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा, 'एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था। लेकिन पहले की सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।'

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक भारत में जैव ईंधन कारोबार 2022 तक 500 अरब रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो अभी 60 अरब रुपये है। इस क्षेत्र में आगे और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण पर भी विचार कर रही है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में निवेश कर इस क्षेत्र को समर्थन दिया जा सके। साथ ही जैव ईंधन संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनियों को 15-20 साल तक के लिए खरीद की गारंटी देने पर भी विचार किया जा रहा है।

विश्व जैव ईंधन दिवस के मौके पर नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018' नामक पुस्तिका जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राधा मोहन सिंह, राम विलास पासवान, हर्षवर्धन और धर्मेंद्र प्रधान फोटो-पीटीआई

# अध्ययन दौरे पर जा रहे सभी वित्तीय सलाहकार

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 10 अगस्त

अगले सप्ताह भारत सरकार के सभी वित्तीय सलाहकार अध्ययन दौरे पर जा रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के करीब 32 सलाहकारों में से सभी अगले डेढ़ सप्ताह तक अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के स्टैनफर्ड स्कूल आफ पब्लिक पॉलिसी, नॉर्थ कैरोलाइना और उसके बाद वाशिंगटन डीसी के ड्यूक कैंपस में रहेंगे।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने कार्यक्रम का जो ब्योरा देखा है, वह 13 से 21 अगस्त तक चलेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की है कि इस कार्यक्रम में भारत सरकार की सेवा कर रहे सभी वित्तीय सलाहकार शामिल होंगे।

ड्यूक स्टैनफर्ड में चलने वाले अध्ययन सत्र में वित्तीय नीति एवं प्रबंधन, सार्वजनिक व्यय, निवेश, पूंजीगत व्यय का प्रबंधन, निजी सार्वजनिक हिस्सेदारी, बजटिंग, परिणाम और प्रदर्शन के मुताबिक बजटिंग, विलय एवं अधिग्रहण, नकदी प्रबंधन और कोषागार का काम जैसे विषय शामिल हैं। ड्यूक स्टैनफर्ड में चलने वाले एक सप्ताह के कार्यक्रम के बाद अधिकारी 20 और 21 अगस्त तक वाशिंगटन डीसी में रहेंगे, जहां वे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों के साथ चलने वाले सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समकक्ष अमेरिका के गवर्नमेंट अकाउंटिबिलिटी ऑफिस (जीएओ) जाएंगे।

विभिन्न विभागों में वित्तीय सलाहकार ज्यादातर भारतीय प्रशासनिक सेवा से लिए जाते हैं, लेकिन भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा सेवा और वित्त सेवा से भी आते हैं।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की वेबसाइट से मिली सूचना के मुताबिक केंद्र सरकार में वित्तीय सलाहकारों के 36 पद हैं, जिनमें से 4 पद खाली हैं। सलाहकारों की सेवा भारत सरकार (वित्तीय सलाहकार से सलाह) नियम 1968 से संचालित है।

वित्तीय सलाहकार जिस विभाग में नियुक्त होता है, उसके वित्त, बजट निर्माण एवं लेखा की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। संबंधित विभाग से सरकारी कंपनियों को धन जारी करने के मामले में भी सलाहकार की राय ली जाती है। स्कॉलरशिप और कर्ज सहित सभी सहायता अनुदान के प्रस्तावों को अनुमति देने के पहले वित्तीय सलाहकार को भेजा जाता है।

मूर्ति चोरी मामले में टीटीएस